RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 20 दिसंबर 2023 वर्ष 05 अंक 237 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मैंने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की खाई है कसम...

सीएम शिंदे का विधानसभा में बड़ा ऐलान

नागपुर: मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जारी सस्पेंस के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। नागपुर में चल रहे राज्य विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी। शिंदे ने कहा यह सत्र फरवरी में होगा। शिंदे ने कहा कि अगले महीने तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह सत्र बुलाया जाएगा।

शिंदे ने सदन में कहा कि मैंने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है। सदन में शिंदे ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में महाराष्ट्र ने देखा है कि जो मैं ठानता हूं, से पूरा करता हूं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जारांगे पाटिल ने सरकार को 24 दिसंबर तक का समय दिया था। पहले ऐसी उम्मीद थी कि सरकार नागपुर के शीतकालीन सत्र में मराठा आरक्षण पर चर्चा कर सकती है। अब सीएम शिंदे ने फरवरी में विशेष सत्र बुलाने का ऐलान विधानसभा में किया है।

OBC को नहीं होग नुकसान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम ओबीसी समुदाय को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने जा रहे हैं। हमने कई बार बात की है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम, संदेह पैदा किया जाता है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। मैंने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेता, भले ही यह शपथ किसी भी समुदाय के लिए होती।

उच्च न्यायालय ने अवैध होर्डिंग पर कदम नहीं उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई...

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मुंबई निवासी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि ये महानगर को बदरंग करते हैं। पीठ ने सवाल किया कि क्या ऐसे मामलों से निपटने के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों का आदेश लागू होगा या उनका, जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। पीठ ने सभी नगर निकायों को अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।वर्ष 2017 से, उच्च न्यायालय राज्य में सरकार और नगर निगमों को अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर रहा है। होर्डिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने मंगलवार को कहा कि सरकार सामान्य आदेशों का भी पालन नहीं कर पा रही है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक हलफनामे में कहा कि पहले के निदेर्शों के अनुसार अवैध होर्डिंग हटाने के समय दो पुलिस कर्मियों को निगम कर्मचारियों के साथ रहना होगा ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होने से बचा जा सके।

डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर केवल एक टिकट... यात्रियों की कतार

डोंबिवली : डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर रेलवे टिकट खिड़कियों पर सुबह के समय पांच से छह टिकट खिड़कियां होती हैं, लेकिन सुबह के समय केवल एक टिकट खिड़की ही रखी जाती है। इस अवधि के दौरान स्वचालित टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से टिकट बेचने वाले निजी विक्रेताओं की अनुपस्थिति के कारण यात्रियों को एकल टिकट खिड़की के सामने खड़े होकर टिकट खरीदना पड़ता है। कई नागरिक सुबह के शुरूआती घंटों में यात्रा करते हैं। अब छुट्टियों का मौसम शुरू हो जाएगा. कई नागरिक इस अवधि के दौरान सुबह जल्दी यात्रा करना पसंद करते हैं। इसलिए जब वे सुबह-सुबह टिकट खरीदने के लिए डोंबिवली रेलवे स्टेशन आते हैं, तो उन्हें केवल एक रेलवे टिकट खिड़की खुली मिलती है।

वसोर्वा-विरार सी ब्रिज परियोजना के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू

मुंबई: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने वसोर्वा-विरार सी ब्रिज परियोजना शुरू कर दी है और इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन मछुआरों, मछुआरा संगठनों ने समुद्री पुल और सर्वेक्षण का कड़ा विरोध किया है. मछुआरों द्वारा सर्वे का काम बंद करने से एमएमआरडीए की चिंता बढ़ गई है. इस पृष्ठभूमि में, एमएमआरडीए ने मत्स्य पालन विभाग से मछुआरों को मनाने के लिए कहा है। एमएमआरडी ने समाधान निकालने के लिए मछुआरों और एमएमआरडीए की संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है।

एमएमआरडीए वसोर्वा-विरार के बीच 42.75 किमी लंबे समुद्री पुल का निर्माण कार्य करेगा। इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना स्थल पर विभिन्न प्रकार के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है. जगह-जगह सर्वे के लिए जा रहे अधिकारी-कर्मचारियों को रोका जा रहा है। मछुआरा भाई सर्वेक्षण बंद कर रहा है। इस बीच मछुआरों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि सी ब्रिज जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को लागू करते समय मछुआरों को विश्वास में नहीं लिया गया है. इस परियोजना से मछली पकड़ने के उद्योग को खतरा होगा। इसलिए मछुआरों से चर्चा करना जरूरी था. लेकिन अखिल महाराष्ट्र मछुआरा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र टंडेल ने आरोप लगाया है कि ऐसा किए बिना ही परियोजना को लागू करने की तैयारी की जा रही है.

वसई विरार की 6 लैब पर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री के निर्देश... हरकत में पुलिस

वसईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वसई विरार में 6 अवैध पैथोलॉजी लैब और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. विधानसभा सत्र में इस संबंध में सवाल उठाये जाने के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया. इस संबंध में नगर पालिका लगातार पुलिस से संपर्क कर रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। वसई विरार शहर में हाल ही में एक प्राइवेट लैब द्वारा मरीजों की जान से खेले गए खेल का खुलासा हुआ था. 6 निजी लैब में खून, मल की जांच रिपोर्ट डॉ. राजेश सोनी के हस्ताक्षर से दी जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि जब सोनी की मान्यता रद्द की गई थी, तब भी वह हस्ताक्षर कर रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे। इससे मरीजों को गलत रिपोर्ट दी जाती थी और उनके स्वास्थ्य को खतरा होता था. इस मामले में नगर पालिका ने 6 निजी लैब संचालकों को नोटिस भेजा था। हालांकि डॉ. राजेश सोनी और अवैध हस्ताक्षर करने वाले 6 लैब संचालकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। मुंबई के दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील प्रभु ने इसे लेकर विधानसभा में सवाल उठाया है. गुजरात में श्रीजी पैथोलॉजी लैब, पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर, गेटवेल क्लिनिकल लेबोरेटरी, ग्लोबल केयर एंड वेलफेयर डायग्नोस्टिक सेंटर और धन्वंतरी लैब्स में गैर-मान्यता प्राप्त डॉक्टरों के हस्ताक्षर कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा गया. इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माना कि यह सच है. महाराष्ट्र मेडिकल कार्उंसिल (महाराष्ट्र मेडिकल कार्उंसिल) को डॉ. राजेश सोनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जो मान्यता रद्द होने के दौरान गुजरात में बैठकर 6 लैब संचालकों को रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को संबंधित 6 लैब चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन सभी 6 प्राइवेट लैब को बंद कर दिया गया है. हालांकि, स्थानीय पुलिस से बार-बार पत्राचार के बावजूद उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. इसलिए अब मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अजिंक्य बागड़े ने इसकी शिकायत पुलिस आयुक्त से की है. इस पत्र में कहा गया है कि इस मामले में कुल 5 बार पत्राचार हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. नगर पालिका ने कार्रवाई के लिए विधानसभा में तारांकित प्रश्न का हवाला भी दिया है। इसलिए अब इस बात पर ध्यान दिया गया है कि पुलिस कब कार्रवाई करती है.

संपादकीय / लेख

पाबंदियों की कृषि नीति

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

प्रधानमंत्री मोदी गरीब, किसान, महिला और युवा को ही ह्याजातियांह्न मानते हैं। हाल के विधानसभा चुनावों में उन्होंने यह खूब प्रचार किया और ह्याजातीय गणनाह्न की सियासत को खारिज किया। वैसे भी किसान और खेती प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में रहे हैं। हालांकि सवाल भी कई उठते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ह्याराष्ट्रीय बॉयोफ्यूल नीतिह्न का श्रेय भी दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने गेहूं, चावल, चीनी और प्याज के निर्यात पर जैसी पाबंदियां थोप रखी हैं और एथनॉल उत्पादन के भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनसे कृषि-व्यापार से जुड़ा प्रत्येक शख्स, किसान और कारोबारी, चीनी मिलें आदि परेशान हैं। एक तरफ पेट्रोल आदि में 11.8 फीसदी तक एथनॉल के मिश्रण का अभियान जारी है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने के रस या सिरप से एथनॉल का उत्पादन न किया जाए। यह कृषि-व्यापार से जुड़े वर्ग के लिए ह्यानीतिगत आघातह्न है। मोदी सरकार का दोगलापन भी सामने आया है कि कमोबेश एथनॉल वाला आदेश सरकार के ही सुधारवादी इरादों और नीतिगत प्रयासों के विपरीत है। बल्कि उन्हें खंडित करता है। कुछ अनाजों पर पाबंदी थोपी गई है, क्योंकि भारत के लिए अपनी खाद्य-सुरक्षा के लक्ष्य पहले जरूरी हैं। देश में गेहूं, चावल, चीनी का संकट नहीं होना चाहिए। यही प्याज पर भी लागू होना चाहिए, जब अचानक प्याज महंगा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?

किसानों को अपनी राष्ट्रीय मंडियों में अपनी फसल का उचित भाव नहीं मिलता, तो कई किसान-समूह अपनी फसल निर्यात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने पाबंदियां थोप रखी हैं। हालांकि सरकार के ऐसे भी निर्देश हैं कि दालों के सीमित भंडार होने चाहिए, लेकिन महंगाई के दौर में जमाखोरों की चांदी होने लगती है और सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती हुई भी नहीं दीखती। निर्यात पर पाबंदी और उत्पादक उतनी ही मात्रा में उत्पादन करें, जितना भंडारण करने की अनुमति है। दरअसल यह उन खेती कानूनों के खिलाफ है, जो सितंबर, 2020 में संसद ने पारित किए थे, लेकिन नवम्बर, 2021 को जिन्हें रद्द करना पड़ा था। एथनॉल के ही संदर्भ में लें, तो गन्ने के रस से एथनॉल पैदा करने के लिए मिल मालिकों ने नई डिस्टिलरियां स्थापित करने में काफी धन का निवेश किया था। गन्ना मिल और किसान आपस में पूरक हैं। अब सरकारी नीति के मद्देनजर व्यापारियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी के राजस्व का भी बलिदान देना पड़ेगा। सरकार के मूल आदेश में संशोधन किया गया है कि मिलों को अब एथनॉल बनाने की अनुमति, गन्ने के सीमित रस अथवा ह्याबी-हैवीह्न गुड़ तक ही, दी जा सकती है। वे 17 लाख टन से ज्यादा गन्ना या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। यह शर्त चीनी मिलों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकती है। एथनॉल ईंधन के लिए कम गन्ने या चीनी के इस्तेमाल के मायने हैं कि आम उपभोक्ता के लिए खाद्य के तौर पर चीनी उपलब्ध रहे। सवाल है कि क्या भारत में चीनी का उत्पादन भी कम हुआ है और आम आदमी के लिए उसके संकट के भी आसार हैं? चीनी के निर्यात पर भी मई माह से पाबंदी है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मानखुर्द-शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र की जनता को आखिर क्यों छोडा लवारिश

क्या अबू आसिम आजमी को विरोधी खेमे का होने का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है

सरकारी जमीन की कमी से विकासकारी परियोजनाएं तोड़ रही दम

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) इन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रदेश भर मे बढ़ते प्रदूषण के स्थर को को लेकर मुंबई मनपा अधिकारियों, पालिका कर्मियों के कार्यो का निरक्षण करने मे लगे है। जिसके चलते आये दिन मुख्यमंत्री मुंबई के विभिन्न रहीवासिया इलाकों का दौरा कर रहे है पर मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा आने से कन्नी काट रहे है । गत दिनों पूर्वी मुंबई मे घाटकोपर, चेंबूर, मुलुंड ,घाटकोपर , कामराज नगर जैसे झुग्गी झोपड़पट्टियों मे जाकर झोपड़पाटी के राहीवासीयो को एस आर ए प्रोजेक्ट जमीन पर उतरकर बिल्डिंगो मे रहने की व्यवस्था कर रहन सहन बदलाव करने मे लगी है । परंतु गोवंडी शिवाजीनगर इलाके के बुधजीवि समाज के लोगों मे इस बात की चर्चा छीड चुकी है की आखिर क्यों राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मानखुर्द शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र की जनता को लवारिश छोड दिया जन समस्याओ के बीच मरने के लिए । मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र मे बड़े पैमाने पर जनसमस्याओ का ढेर लगा हुआ है । एम/पूर्व विभाग की सरकारी जामिनो पर भ्रस्ट चेंबुर कलेक्टर कार्यलय से लेकर एम पूर्व मनपा विभाग की सहायक आयुक्त अलका सासाने, जोन पांच मनपा उपायुक्त हर्षद काले, म्हाडा , एम.एम. आर.डी.ए की रिक्त के अधिकारियों की भूमाफियाओ के साथ जुगल बंदी के कारण लिंक रोड़ की दोनों ओर कथित सरकारी जामिनो पर कब्जा कर झोपड़े, दुकान, गोदामो को बना कर लाखों रुपए मे बेचने का गोरख धंधे को संरक्षण दे रखा है। सरकारी जमीन की कमी से विकासकारी परियोजनाएं तोड़ रही दम। बताते है की। एम पूर्व विभाग बड़े पैमाने पर विकास के मामले मे काफी पिछडा इलाका है । एम पूर्व मनपा का परिसर मे स्वछता के नाम पर डंपिंग के कचरे , गंदगी से भरे हुए इलाके मे नागरिको को एस एम एस कंपनी के जहरीले प्रदुषण मे सांस लेने के लिए मरने को छोड़ दिया है ।एम पूर्व विभाग मे बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज,गार्डन, खेल के मैदान, सुलभ शौचालय आबादी के अनुपात के हिसाब से नागरिको की सुविधा बहुत कम है।

कोरियाई व्लॉगर के साथ अश्लील हरकत...

मुंबई : महाराष्ट्र में कुछ स्थानीय लोगों ने साउथ कोरियाई यूट्यूबर और व्लॉगर केली के साथ सरेआम बदसलूकी की। यह बेशर्म हरकत केली के कैमरे में भी कैद हो गई। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दक्षिण कोरियाई व्लॉगर को लोकल मार्केट में दो लोग परेशान करते दिख रहे है।

यह घटना तब हुई जब दक्षिण कोरियाई यूट्यूबर कुछ दुकानदारों के साथ पोज दे रही थीं। तभी एक शख्स ने उन्हें गले से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि व्लॉगर मार्केट में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर रही थी और अपना अनुभव साझा कर रही थी। इसे रिकॉर्ड करने के लिए केली ने अपना कैमरा चालू रखा था। तभी दो लोग अचानक उसके पास आए और उनमें से एक युवक ने केली के कंधे पर हाथ रख दिया और गर्दन दबाकर गले लगाने की कोशिश की। हालांकि जल्दी ही केली खुद को उनके पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और उन्हें अलविदा कहकर तेजी से आगे बढ़ जाती है।

केली ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें वह घटना के बाद डरकर वहां से तेजी से जाती दिख रही है। केली ने कहा, 'न जाने क्यों लोगों को गले लगना पसंद है। मुझे यहां से जल्दी भागना होगा।' वीडियो में केली कहती नजर आ रही हैं, ह्यामुझे यहां से भागना होगा।ह्न उन्होंने पिछले हफ्ते अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट किया था। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, कोरियाई पर्यटक के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।

40 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त... चेकिंग में सफेद पाउडर से भरे दो बैग मिले

मुंबई : मुंबई में सिएरा लियोन से नशीले पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई के अधिकारियों ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। अधिकारियों को उसके बैग की चेकिंग में सफेद पाउडर से भरे दो बैग मिले। टेस्टिंग के बाद इस सफेद पाउडर के कोकीन होने की पुष्टि हुई। दोनों पैकेट्स में चार किलो कोकीन पकड़ी गई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपये बताई गई है। इन्हें एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया। वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गुप्त जानकारी के आधार पर डीआरआई की एक टीम ने मुंबई एयरपोर्ट के करीब एक होटल के कमरे में तलाशी ली थी। बयान के मुताबिक, सिएरा लियोन से आए यात्रियों में से एक पर डीआरआई की नजर थी, क्योंकि एजेंसी को संदेह था कि उसने भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की थी।

डीआरआई ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बयान के मुताबिक, आरोपी जिस मादक पदार्थ गिरोह से जुड़ा है, उसके प्रमुख सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच की जा रही है।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : बुधवार 20 दिसंबर 2023

तीन दिन से नहीं उठ रहा था कचरा, डांपिग ग्राउंड में लगा दी आग?

राज्य मानवाधिकार आयोग लगा चुकी है फटकार...

भिवंडी : भिवंडी शहर महानगर पालिका परिक्षेत्र अंर्तगत कचरा पॉइंटों से लगातार तीन दिनों से कचरा नहीं उठाऐ जाने से लोगों ने अब जमा कचरे की ढेर में आग लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक घटना तीनबत्ती सब्जी बाजार के पास बनाऐ गये अवैध डांपिग ग्राउंड में सोमवार देर शाम घटित हुई है। इस अवैध डंपिंग ग्राउंड में छोटी गाडियों से कचरा इकठ्ठा कर बड़ी गाडियों से डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। परन्तु शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार तीन दिनों तक छोटी गाडियों ने यहां विभिन्न क्षेत्रों से कचरा लाकर डंप किया था। जिसे बड़े वाहनों से डांपिग ग्राउंड तक पहुंचाया जाना था। किन्तु पिछले तीन दिनों से बड़ी गाडियों द्वारा कचरा नहीं उठाया गया। जिसके कारण भारी मात्रा में कचरा इकठ्ठा हो चुका था। सोमवार शाम के समय अज्ञात व्यक्ति ने इस कचरे की ढेर में आग लगा दी। जिसके कारण आसपास लगभग आधे किलोमीटर क्षेत्र में जहरीला धुआ फैल गया था। इस धुऐ से लोगों में सांस लेने में दिक्कत होनी लगी थी। किन्तु ताज्जुब की बात है कि कई घंटे तक

डांपिग ग्राउंड की आग बुझाने के लिए पालिका के अग्निशमन विभाग की दमकल गाडियां नहीं पहुंची। जिसके कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। भिवंडी शहर महानगर पालिका की मुख्य सड़कें व रहिवासी बस्तियों में जमा कचरा व उबड खाबड़ सड़कों के हो रही दुर्घटनाऐ संबंधी समस्या क राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वयं संज्ञान में लिया है तथा पालिका प्रशासन को नोटिस जारी कर तलब किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जैन से शहर के जमा कचरे की ढेर, खस्ताहाल सड़कें की तस्वीरें लगाकर शपथ पत्र देकर शहर की हकीकत से मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया है।

पालिका प्रशासन के भष्ट्राचार रवैया व लापरवाही से छोटे व बड़े व्यापारी दोनों शासन द्वारा प्रतिबंधित किये गये प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल कर रहे है। इन प्रतिबंधित थैलियों में सूखा व गीला कचरा भर कर कचरा पॉइंटों पर फेक दिया जाता है। सब्जी मार्केट के पास बने अवैध डांपिग ग्राउंड में भारी मात्रा में प्लास्टिक थैलियों में कचरा भरा हुआ था। जिसमें आग लगने से धूआ जहरीला हो गया था। हालांकि पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक थैलियों की धर पकड़ करने के लिए 11 सदस्यों वाली एक पथक तैयार किया है। परन्तु पथक द्वारा कार्रवाई ना करने से बड़े पैमाने पर सब्जी विक्रेताओं से लेकर फल, मांस विक्रेता व दुकानदार इन थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार तीन दिनों से कचरा ठेकेदार द्वारा कचरा नहीं उठाया गया।

गोरेगांव मुलुंड परियोजना की लागत 47 करोड़ रुपये बढ़ेगी...

स्थानांतरण के कारण लागत में वृद्धि

मुंबईः गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट की लागत और बढ़ गई है. परियोजना स्थल पर सड़क के नीचे उपयोगिता चैनलों को स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त 47 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिससे परियोजना की मूल लागत 666 करोड़ रुपये से बढ़कर 713 करोड़ रुपये हो जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत सात फीसदी बढ़ गई है और सभी टैक्स समेत प्रोजेक्ट की लागत 862 करोड़ हो जाएगी.

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. गोरेगांव-मुलुंड एक्सप्रेसवे नगर पालिका की एक प्रमुख परियोजना है और इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाला चौथा एक्सप्रेसवे मुंबईकरों के लिए उपलब्ध होगा। इस अत्यंत जटिल परियोजना को चार चरणों में व्यवस्थित किया गया है।

इनमें तीसरे चरण में गोरेगांव में रत्नागिरी होटल के पास 1265 मीटर लंबे छह स्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण, मुलुंड खिंडीपाड़ा में उच्च स्तरीय साइकिल एलिवेटेड रोड का निर्माण और डॉ. हेडगेवार चौक पर 1890 मीटर लंबे छह स्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा। इन तीन पुलों के लिए एस. पी। सिंगला कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड दिसंबर 2021 में उन्हें 666 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. फिलहाल ये काम चल रहा है और अब इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है.

प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सीमेंट प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की मांग...

मुंबईः शहर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक ओर जहां नगर पालिका तरह-तरह के अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर चेंबूर में विशेष सामाजिक न्याय एवं सहायता विभाग के परिसर में धूल का विशाल साम्राज्य फैल गया है. यहां सीमेंट प्लांट की वजह से प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं और चेंबूर के निवासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अधिकारी और निर्माण विभाग इस प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में हैं. चेंबूर क्षेत्र के वाशिनाका, माहुल इलाके में केमिकल और पेट्रोलियम कंपनियों के कारण पूरे चेंबूर क्षेत्र में वायु और धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण अब तक कई नागरिक इसका शिकार बन चुके हैं। नगर निगम आयुक्त और

राज्य सरकारें वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही हैं। इसमें स्वच्छ अभियान, 'डीप क्लीनिंग' अभियान भी शामिल है। इसमें नगर निगम प्रशासन, आयुक्त, मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं. उधर, चेंबूर स्थित सामाजिक न्याय विभाग के परिसर में कई दिनों से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बगल में ही सीमेंट मिक्सर प्लांट चल रहा है। इस प्लांट से अन्य स्थानों पर सीमेंट की आपूर्ति की जा रही है। यहां दिन-रात सीमेंट से भरे ट्रकों का आना-जाना लगा रहता है। अंतरिम में नगर पालिका ने धूल को रोकने के लिए नियम तैयार किए थे; लेकिन, अनुपालन नहीं होने के कारण इस सड़क और इलाके में बड़ी मात्रा में सीमेंट की धूल फैल गयी है. निवासियों का आरोप है कि नगर निगम एम वेस्ट के अधिकारी और निर्माण विभाग निष्क्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चेंबूर इलाके में एल. यू 2013 से 2017 तक चार साल तक गडकरी मार्ग पर अमित बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई प्रा.लि. लिमिटेड कंपनी द्वारा अवैध रूप से आरएमसी सीमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा था। इस क्षेत्र के नागरिकों ने नगर पालिका से इस प्लांट को बंद करने की मांग की थी। तदनुसार इसे बंद कर दिया गया; लेकिन अब फिर से इस इलाके में सीमेंट प्लांट शुरू कर दिया गया है.

मुंबईः वाहन चोरी के मामले में मध्य प्रदेश से दो गिरफ्तार...

मुंबईः डिंडोशी पुलिस ने मध्य प्रदेश से दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो वाहन चोरी कर ग्राहकों की मांग पर बेच रहे थे। आरोपियों के पास से चोरी की पांच कारें बरामद की गई हैं और उनकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये है. इन दोनों पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से वाहन चोरी करने का संदेह है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वसीम अल्ताफ पठान (37) और शाहिद अयूब खान (34) के रूप में हुई है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. पठान के खिलाफ वाहन चोरी के छह मामले दर्ज हैं। 2 दिसंबर को, पुलिस ने डिंडोशी पुलिस सीमा के अंतर्गत रहेजा आईटी पार्क क्षेत्र में एक मोटर चालक को तेज गति से गाड़ी चलाते देखा। जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया तो वह तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया. जब चालक और उसके साथी से पूछताछ की गई तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। जब उसकी गाड़ी के कागजात चेक किए गए तो वह फर्जी पाए गए।

भुजबल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत ! बेनामी संपत्तियों से जुड़ी 4 शिकायतें रद्द

मुंबई : एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बेनामी हेराफेरी को लेकर भुजबल परिवार के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर की गई 4 शिकायतों को खारिज कर दिया है। ये संपत्तियां छगन भुजबल, समीर और पंकज भुजबल की थीं। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी निषेध अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज की गईं। साथ ही, सितंबर 2021 में

आयकर विभाग ने विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की और संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (जब्त) कर लिया। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि भुजबल परिवार ने लगभग 4 दर्जन फर्जी कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्ति अर्जित की। 17 नवंबर, 2021 को मजिस्ट्रेट ने आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर भुजबल परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। इस बीच भुजबल और उनके परिवार की कंपनियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद जस्टिस आरएन लाजधा की एकल पीठ ने आयकर विभाग की इन शिकायतों को खारिज कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर दिया गया है कि 2016 का कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होता है। शिकायतों को रद्द करने के साथ-साथ अदालत ने छगन भुजबल के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। यह मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है।

10 साल बाद शुरू होगी 15 लाख मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए ठेकेदार को टास्क ऑर्डर

वसईः वसई विरार नगर निगम की कचरा भूमि पर जमा कचरे के पहाड़ अब साफ होने वाले हैं। नगर पालिका ने जमा हुए 15 लाख मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए ठेकेदार को टास्क ऑर्डर जारी कर दिया। 2013 के बाद यह पहली बार है कि ऐसी प्रक्रिया होगी। वसई विरार शहर में बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आमतौर पर गोखिवरे भोयदापाड़ा लैंडफिल में हर दिन 750 से 800 मीट्रिक टन कचरा डंप किया जाता है। 2013 में, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट परियोजना को बंद कर दिया गया था। तब से, समस्याएँ उत्पन्न हुईं क्योंकि इस कचरे के प्रसंस्करण और निपटान के लिए कोई परियोजना नहीं थी।

इधर इस बढ़ते कचरे के कारण बंजर भूमि की जगह भी अपर्याप्त होती जा रही है। इसके चलते मौजूदा स्थिति में एक के बाद एक कूड़े के ढेर लगने लगे। मूलतः प्रतिदिन कूड़े-कचरे का जमाव और उसमें पहले से ही जमा कूड़े के पहाड़ों ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इस समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका ने इस जमा हुए कचरे को बायोमाइनिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2 से 46 करोड़ की धनराशि मिलेगी. बायोमाइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़े काम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह काम एक निजी कंपनी साई यूटिलिटी को दिया गया है. इस संबंध में कार्यादेश सोमवार को नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग से संबंधित ठेकेदार को ले लिया गया है। यह ठेका अगले बीस वर्षों के लिए होगा।

इस तरह कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा

यह काम डिमांड बिल्ड फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओ) के आधार पर किया जाएगा। पहले चरण में बंजर भूमि पर पड़े 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार कर उसे साफ किया जाएगा। इसमें दो साल लगेंगे. इसमें दो साल लगेंगे. उक्त स्थल पर परियोजना के लिए आवश्यक भवन निर्माण, मशीनों और अन्य सामग्रियों की खरीद, जनशक्ति आदि की लागत संबंधित कंपनी के माध्यम से की जाएगी और लागत शुरू होने के बाद संबंधित कंपनी को टिपिंग शुल्क के माध्यम से शामिल की जाएगी। परियोजना की। उपायुक्त (ठोस अपशिष्ट) डॉ. चारुशी को पंडित ने बताया है.

इस साल पहली बार वसई विरार नगर निगम ने हाल ही में एक पर्यावरण रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कचरे की समस्या को लेकर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि शहर में प्रतिदिन कूड़ा उठाव कर कूड़ा भूमि तक पहुंचाने के बाद भी जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है. बताया गया कि लगभग 50 फीसदी कूड़ा इधर-उधर पड़ा रहता है.

44 मकानों के निर्माण के लिए म्हाडा को है जमीन का इंतजार, रायगढ़ जिला कलेक्टर से की जमीन की मांग

मुंबईः महाड के पास तलिये में कोंढालकरवाड़ी ने इस क्षेत्र के दरार प्रभावित और खतरनाक क्षेत्रों के निवासियों के लिए तलिये में 271 घरों की एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में दरार पीड़ितों के 66 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 134 मकानों का कार्य प्रगति पर है। आने वाले महीनों में 27 मकानों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कोंकण मंडल को 271 में से 44 घरों के लिए जगह नहीं मिली है. कोंकण मंडल ने रायगढ़ जिला कलेक्टर से इन घरों के लिए जल्द से जल्द जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

22 जुलाई, 2021 को तलिये के कोंढालकरवाड़ी में भूस्खलन हुआ, जिसमें 87 लोगों की मौत हो गई। कोंढालकरवाड़ी में 66 घर मिट्टी धंसने से दब गए। इस त्रासदी के बाद दरार पीड़ितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सौंपी गई। घर बनाने की जिम्मेदारी म्हाडा के कोंकण मंडल को सौंपी गई थी।

प्रभादेवी में आर्थिक विकास पर सेमिनार

प्रभादेवीः भारत के आर्थिक विकास में मध्यस्थता की मौलिक भूमिका का पता लगाने के लिए कानून, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए 'मध्यस्थता' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए) में 'आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में मध्यस्थता' पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, आईसीए के महानिदेशक अरुण चावला, आईसीए के अध्यक्ष और खेतान कंपनी के वरिष्ठ साझेदार एन. जी। वक्ताओं में आईसीए के उपाध्यक्ष खेतान और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने अपने विचार व्यक्त किये।

ठाणे में जल वितरण सुधार परियोजना लागत में वृद्धि

ठाणेः केंद्र सरकार की अमृत योजना के माध्यम से ठाणे, कलवा, मुंब्रा, दिवा के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिए ठाणे नगर निगम द्वारा नियोजित जल वितरण प्रणाली सुधार परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 323 करोड़ रुपये मानी गई थी. लेकिन प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद इसमें साढ़े चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी. इस परियोजना के शुरूआती टेंडर में कुछ कार्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, इन कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने परियोजना लागत को छह से सात प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया था। लेकिन नगर पालिका ने साढ़े चार प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन चार स्रोतों से 585 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है. इसमें नगर निगम की अपनी योजना से 250 मिलियन लीटर, एसटीईएम प्राधिकरण से 115 मिलियन लीटर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से 135 मिलियन लीटर और मुंबई नगर निगम से 85 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। हालांकि शहर को प्रतिदिन 585 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन शहर के कई हिस्सों में पानी की कमी की शिकायतें आती रहती हैं। यह पता चला कि पानी की कमी की समस्या जल वितरण प्रणाली में खराबी और पुराने जलसेतुओं के कारण पानी के रिसाव के कारण थी। इस पृष्ठभूमि में, नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति और वितरण प्रणाली को मजबूत और विस्तारित करने का निर्णय लिया था और ऐसा प्रस्ताव तैयार किया था।

अंतर-स्कूल प्रतियोगिता के विजेताओं को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया

कांदिवलीः कांदिवली अनुभाग में धार्मिक कथाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इस आयोजन के विज्ञापन के लिए चौकों का इस्तेमाल किया गया है. इसमें एस. वी रोड, एम. जी। इन कार्यक्रमों के बैनर रोड और लिंक रोड इलाके के चौराहों और सिग्नल एरिया पर लगाए गए हैं. नगर पालिका ने लाखों रुपये खर्च कर चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया है; लेकिन बैनरबाजी के कारण इन चौराहों की हालत खराब हो गई है। इसलिए नागरिकों की मांग है कि नगर निगम बैनर पर तुरंत कार्रवाई करे और चौराहे को खाली कराए.

'इंटर-स्कूल प्रतियोगिता 2023' प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण

घाटकोपरः महर्षि आबासाहेब बंदगर की चौदहवीं वर्षगांठ पर 'इंटर-स्कूल प्रतियोगिता 2023' प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह हाल ही में घाटकोपर पश्चिम में आयोजित किया गया था। अंतर-विद्यालय प्रतियोगिता छात्रों की बुद्धि और कल्पना को उत्तेजित करती है।

सिद्धनाथ शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष विशाल बंडगर ने कहा कि यह बच्चों के समग्र विकास में मदद करता है। ये प्रतियोगिताएं सरस्वती विद्यानिकेतन में आयोजित की गईं। इसमें घाटकोपर, विक्रोली डिविजन के करीब 15 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस समय ज्ञानप्रकाश विद्यालय, पुणे विद्या भवन नं. -2 और पुणे विद्या भवन हाई स्कूल ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। विजेता प्रतियोगियों को संस्थान के अध्यक्ष विशाल बंदगर, आर. जी। हुले, डॉ. रत्नदीप दलवी द्वारा सम्मानित किया गया।

सस्ते डॉलर देने का झांसा... 2 लाख की धोखाधड़ी

नवी मुंबईः अमेरिकी मुद्रा के साथ सस्ते डॉलर देने का झांसा देकर नवी मुंबई के घनसोली में 2 लाख की धोखाधड़ी हुई। इस संबंध में रबाले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस कार्यालय ने दर्ज किया है कि आरोपियों की पहचान अनवर और एक बीस वर्षीय युवक के रूप में हुई है. वादी का नाम गुलफाम आलम अफसर अली है और वह कांदिवली का रहने वाला है। उसके परिचित एक नारियल विक्रेता ने उसे 20 डॉलर का नोट दिखाया। कुछ दिन पहले एक फोन आया और फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह नारियल बेचने वाले का भाई है और जैसे ही भाई ने नोट दिखाया, उसने बताया कि उसके पास 20-20 के एक हजार सात सौ पचास डॉलर के नोट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आवश्यकता के कारण इस नोट के बदले भारतीय रुपये चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका एक रिश्तेदार 2 लाख भारतीय रुपये के बदले यह डॉलर देने को तैयार है.

पनवेल में व्यायाम करने वालों की संख्या बढ़ी, सुबह ठंडा मौसम... कई जिम, पार्कों में भीड़

पनवेलः राज्य में पिछले कुछ दिनों से सर्दी पड़ रही है. इसके चलते सुबह की ठंड में व्यायाम करने के लिए युवाओं और बुजुर्गों की भीड़ बढ़ गई है। बरसात के मौसम की समाप्ति के बाद, दिवाली एक ठंडी और गुलाबी सर्दी लेकर आती है। इस बीच पनवेलकर गर्मी से परेशान हो रहे थे. लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस दौरान एक्सरसाइज करने का मजा ही अलग होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में स्वस्थ वातावरण रहता है। इसलिए अच्छा व्यायाम जरूरी है. इसके चलते शहर के जिम और जॉगिंग पार्कों के साथ-साथ सड़कों पर भी भीड़ हो गई है। खारघर, करंजदे, टी-प्वाइंट के पास की पहाड़ी, नहाव शेवा, सेंट्रल पार्क रोड, सेंट्रल पार्क और कॉलोनी के खुले भूखंडों में बड़ी संख्या में नागरिक ठंडी सुबह में व्यायाम का आनंद लेते देखे जाते हैं। कुछ स्थानों पर नागरिक समूहों में व्यायाम करते देखे जाते हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com